



2026:AHC:176471

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7462 वर्ष

2026

संदीप कुमार शाह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनुज कुमार श्रीवास्तव, नरेंद्र मोहन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : चन्द्र भूषण द्विवेदी, जी.ए., योगेश कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव के साथ श्री नरेंद्र मोहन, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान एजीए की बातें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. यह उसी मुकदमा अपराध में दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन है। प्राथमिकी 13.11.2025 को बीएनएस की धारा 69, 351(3) और 352 के तहत दर्ज की गई थी। आवेदक ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1276/2026 दायर की थी और इस न्यायालय की संबंधित पीठ ने 16.02.2026 के आदेश से अंतरिम सुरक्षा दी थी। ठीक से विवेचना के बाद, विवेचनाधिकारी ने 26.02.2026 को भादंस की धारा 376, 504 और 506 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद, 04.05.2026 के आदेश से उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को निष्फल मानते हुए खारिज कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया गया। भादंसं की धारा 376, 504 और 506 के तहत 26.02.2026 को आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, मुकदमा अपराध संख्या 450/2025 (धारा 376, 504, 506 भादंसं, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बलिया) में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दूसरी/मौजूदा अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया गया है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि सूचनाकर्ता-पीड़िता ने एक झूठी और बेबुनियाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि शादी का झूठा वादा करके उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता ने खुद माना है कि वह बालिग है, उसकी उम्र लगभग 25 साल है और वह पिछले डेढ़ साल से आरोपी के संपर्क में थी; इस दौरान दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध थे। आगे यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी रिश्ते के टूटने का नतीजा है और यह तब दर्ज कराई गई जब उनके बीच रिश्ते खराब हो गए। पीड़िता का बयान बार-बार बदलता रहा है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण पर ज्यादा भरोसा नहीं होता।

4. अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का बयान चिकित्सीय साक्ष्यों से मेल नहीं खाता। यह भी कहा गया है कि डेढ़ साल की लंबी अवधि के दौरान, पीड़िता ने आरोपी द्वारा किए गए कथित यौन शोषण के बारे में पूरी तरह चुप्पी साधे रखी, और यह बात तब सामने आई जब उसे पता चला कि आरोपी उससे शादी नहीं करने वाला है। इसके अलावा, कथित यौन संबंध की पहली घटना और प्राथमिकी दर्ज होने तक डेढ़ साल तक चले रिश्ते के बीच का लंबा समय यह साफ करता है कि प्रकरण प्रेम संबंध का है। जब रिश्ते खराब हुए, तो पीड़िता ने गलत इरादों से प्राथमिकी दर्ज कराई। दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक प्रकरण में बदल दिया गया है।

5. आरोपी के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आरोपी विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आरोपी को अग्रिम जमानत मिलती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।



6. दूसरी ओर, एजीए ने अग्रिम जमानत की आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, उन्होंने तथ्यों से जुड़ी बातों पर कोई विवाद नहीं किया है।

7. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, उस व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जैसे साक्षियों को डराना-धमकाने की संभावना, और न्याय से भागने, जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदन देने वाले की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

9. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या साक्षियों को प्रभावित करने या आरोपी के भाग जाने की संभावना हो। सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी करना विधिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति होने और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच फ़र्क किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अगर विवेचनाधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और असल में उसने विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

10. **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2024) 11 उच्चतम न्यायालय वाद 398** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब कोई महिला जान-बूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाती है, तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे संबंध



केवल शादी के कथित वादे के कारण थे। शादी के वादे के अलावा भी किसी महिला के शारीरिक संबंध बनाने के कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद।

11. **प्रशांत बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य (2025) 5 उच्चतम न्यायालय वाद 764** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह सोचना भी मुश्किल है कि सूचनाकर्ता अपनी मर्जी से सहमति के बिना आरोपी से मिलती रहेगी या उसके साथ लंबे समय तक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

12. इसके अलावा, **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार इस चिंताजनक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है जिसमें असफल या टूटे हुए रिश्तों को अपराध का रूप दे दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, जो सबसे गंभीर अपराधों में से एक है, केवल उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जहाँ वास्तविक यौन हिंसा, ज़बरदस्ती या स्वतंत्र सहमति का अभाव हो। हर खराब रिश्ते को बलात्कार के अपराध में बदलने से न केवल अपराध की गंभीरता कम होती है, बल्कि आरोपी पर कभी न मिटने वाला कलंक भी लगता है और उसके साथ घोर अन्याय होता है। ऐसे प्रकरण केवल व्यक्तिगत झगड़ों के दायरे से कहीं आगे होते हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए गहरी चिंता का विषय है, जो पहले से ही भारी बोझ का सामना कर रही है, और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य 2025 (4) एससीसी 197** प्रकरण में यह माना गया कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रहती है और उसे रिश्ते की असलियत का पूरा पता है, और इस बात का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि यह रिश्ता किसी गलतफहमी या शुरू से ही बुरी नीयत से शादी के झूठे वादे के कारण बना था, तो उस पुरुष को भादंस की धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14. **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 154** प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भादंस की धारा 376(2)(ढ) के तहत दर्ज मामलों में असली मामलों की पहचान करते समय अदालतों को बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए और अपराध के लिए ज़रूरी तत्वों को पहचानना चाहिए। ऐसे असली मामलों को उन



मुकदमों से साफ़ तौर पर अलग किया जाना चाहिए जो आपसी सहमति से बने रिश्तों के बाद विवाद, असहमति या बाद में मन बदलने के कारण कड़वाहट में बदल जाते हैं।

15. रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1055

प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर दो समझदार वयस्क लंबे समय तक शारीरिक संबंध रखते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से आपसी सहमति वाला रिश्ता चुना था और बाद में शादी का वादा पूरा न करने पर कोई अपराध नहीं बनता।

16. प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य ((2019) 9 उच्चतम न्यायालय वाद

608 प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि अगर शादी का वादा झूठा है और वादा करने वाले की नीयत शुरू से ही उसे पूरा करने की नहीं थी, बल्कि महिला को धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करना था, तो यह "तथ्य का भ्रम" है जो महिला की "सहमति" को अमान्य कर देती है। हालाँकि, सिर्फ़ वादा तोड़ने को झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। इसलिए, झूठा वादा साबित करने के लिए यह दिखाना होगा कि वादा करने वाले की, वादा करते समय अपनी बात निभाने की कोई मंशा नहीं थी।

17. सोनू उर्फ़ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2021) 18 एससीसी 517 प्रकरण

में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने पाया कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और वे डेढ़ साल तक रिश्ते में रहे थे। बाद में, आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई।

18. अग्रिम ज़मानत से जुड़े स्थापित विधिक सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों,

आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह पाया गया कि आवेदक का प्रकरण ऊपर बताए गए फैसलों के दायरे में पूरी तरह आता है; इसलिए, अग्रिम ज़मानत का प्रकरण बनता है।

19. इसलिए, अग्रिम ज़मानत आवेदन को इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर आवेदक - संदीप कुमार शाह, जो ऊपर बताए गए प्रकरण में शामिल है, को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए



उसे 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही रकम की दो प्रतिभू देनी होंगी, जो संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय को स्वीकार हों;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी का सहयोग करेगा और विवेचना के मकसद से जरूरत पड़ने पर विवेचनाधिकारी के सामने पेश होगा;

(iii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी न दे; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

20. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, लोक अभियोजक/विवेचनाधिकारी/सूचनाकर्ता को यह अधिकार है कि वे संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दाखिल कर सकें।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

20 अगस्त, 2026

नितेंद्र